

घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर,तर्ष 22, अंक - 333- सोमवार 05- अक्टूबर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीकरण. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

आंध्र प्रदेश में तीन लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे पक्के घर 3,600 करोड़ रुपये की मंजूरी



नई दिल्ली, 04 अक्टूबर 2026। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बुरिपालेम गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 2.0 के तहत तीन लाख घरों की पहली किस्त सौंपने की शुरुआत की। इन घरों के निर्माण पर 3,600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस मौके पर उन्होंने देश की पहली 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक आधारित आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना के तहत 14 करोड़ रुपये की लागत से 177 घर बनाए जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, आंध्र प्रदेश के लिए पहले 76 हजार घरों का आवंटन प्रस्तावित था। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर तीन लाख घर कर दिया। चौहान ने कहा कि तीन लाख घरों का निर्माण पूरा होने के बाद केंद्र सरकार राज्य के लिए तीन लाख और घर मंजूर करेगी। तीन लाख और घर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। चौहान ने बुरिपालेम और ओबुलनायडुपालेम में 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग आधारित आवास परियोजना को ग्रामीण आवास के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ रुपये की इस पायलट परियोजना में आधुनिक मशीनों और 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। इससे निर्माण समय, लागत और श्रम की जरूरत कम होगी। 177 घरों का निर्माण छह महीने में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अमरावती के विकास के लिए भी सहयोग कर रही है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी के रूप में अमरावती को मान्यता देने के लिए संसद में कानून पारित किया और इसके विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता दी है। उन्होंने पोलावरम सिंघाई परियोजना को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे केंद्र से 100 प्रतिशत अनुदान सहायता मिल रही है। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र से किसानों को सालाना छह हजार रुपये और आंध्र प्रदेश सरकार की 'अन्नदाता सुखीभव' योजना के तहत 14 हजार रुपये की सहायता मिलाकर किसानों को हर वर्ष 20 हजार रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश फलों, फूलों, सब्जियों और औषधीय फसलों के क्षेत्र में देश का प्रमुख बागवानी केंद्र बन सकता है।

पेंशन अदालत में 897 लंबित शिकायतों का होगा निपटारा, अति वरिष्ठ और पारिवारिक पेंशनरों के मामलों पर रहेगा जोर

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर 2026। केंद्र सरकार की 17वीं पेंशन अदालत में अति वरिष्ठ पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की 897 लंबित शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 05 अक्टूबर को यहां भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। यह पेंशन अदालत 24 मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए आयोजित की जा रही है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, पेंशन अदालत केंद्रीय सरकारी पेंशनरों की शिकायतों के मौके पर निपटारे के लिए शुरू की गई वैकल्पिक व्यवस्था है। इसमें किसी शिकायत से जुड़े सभी पक्षों को एक मंच पर लाकर लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान किया जाता है। इससे महंगी और समय लेने वाली न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता कम होती है। विभाग ने 2017 में पेंशन अदालत की शुरुआत की थी। अब तक इसके 16 आयोजन हो चुके हैं। इनमें कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 का मौके पर निपटारा किया गया। इसकी सफलता दर 71.79 प्रतिशत रही है।



सैनिक का पार्थिव शरीर लेकर लौट रही एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, पुत्र समेत 4 लोगों की मौत...

एक ही परिवार में जवान की मौत के बाद बेटे समेत तीन अन्य की जान गई, रुद्रपुर में पसरा मातम

देवरिया, 04 अक्टूबर 2026। चंडीगढ़ से सेना के जवान सुबेदार सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर लेकर देवरिया आ रही एंबुलेंस रविवार सुबह सुलतानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एंबुलेंस में सवार जवान के पुत्र हल्लु सिंह, रुद्रपुर नगर पंचायत के सभासद राजन चौधरी, उनके छोटे भाई राम सुमित सिंह और चालक जसपाल की मौत पर ही मौत हो गई। एक ही परिवार में पहले जवान की मौत और इसके बाद उनके पुत्र समेत तीन अन्य लोगों की सड़क हादसे में मौत से रुद्रपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुःख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुःखद है। उन्होंने शोककाल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। भौगोलिक संदर्भ पुलिस के अनुसार, देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के गहिला-दुधैला गांव निवासी सत्यवान सिंह (50) सेना में जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) के

पद पर मेरठ में तैनात थे। शुक्रवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आर्मी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सेना की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर एंबुलेंस से पैतृक गांव रुद्रपुर लाया जा रहा था। बताया गया कि एंबुलेंस में चालक जसपाल के अलावा सत्यवान सिंह के पुत्र हल्लु सिंह, रुद्रपुर नगर पंचायत के सभासद राजन चौधरी और उनके छोटे भाई राम सुमित सिंह सवार

थे। रविवार सुबह सुलतानपुर जिले के हलियापुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अचानक एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार और परिचितों के कोहराम मच गया। जिस परिवार में कुछ ही घंटे पहले सत्यवान सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, उसी परिवार को उनके पुत्र हल्लु सिंह की मौत की खबर ने झकझोर दिया। परिवार के तीन अन्य सदस्य निजी वाहन से एंबुलेंस के पीछे आ रहे थे।

हादसे की जानकारी मिलते ही वे घटनास्थल की ओर रवाना हुए। हादसे में जान गंवाने वाले राम सुमित सिंह रुद्रपुर क्षेत्र के तरसारा डाकघर में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत थे। उनके निधन की खबर मिलते ही डाक विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में शोक छर गया। वहीं, रुद्रपुर नगर पंचायत के सभासद राजन चौधरी की मौत की सूचना से नगर पंचायत क्षेत्र में भी मातम पसर गया। एक ही हादसे में चार लोगों की मौत की खबर फैलते ही रुद्रपुर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मृतकों के परिजनों के घर पहुंचने लगे। पूरे क्षेत्र में शोक और मातम का माहौल है। लोग इस हृदयविदारक घटना से स्तब्ध हैं। इस घटना ने एक परिवार को एक साथ कई अपनों के खोने का ऐसा दर्द दिया है, जिसने पूरे रुद्रपुर क्षेत्र को झकझोर दिया है। जवान के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच हुई इस दुर्घटना से गांव और आसपास का माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया है। हलियापुर थाना के उपनिरीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र निवासी सत्यवान सिंह का निधन होने के बाद उनका पार्थिव शरीर चंडीगढ़ से लखनऊ के रास्ते देवरिया ले जाया जा रहा था।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे का मुंबई में प्रदर्शन बोले...ये बीजेपी का हथियार हैं, इस्तीफा मांगा, सीईसी के खिलाफ 3 दिन में तीन प्रदर्शन

मुंबई, 04 अक्टूबर 2026। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रविवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने जाईंट प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। दोनों नेताओं ने मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर महानगरपालिका भवन तक मार्च निकाला। उद्धव की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में हुए एसआईआर को रद्द किया जाए। सरकार किसकी बनेगी, ये फैसला जनता को तय करना है, चुनाव आयोग को नहीं। वहीं उद्धव बोले कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी का हथियार हैं।

महाराष्ट्र में एसआईआर प्रक्रिया रद्द की जाए : राज ठाकरे

हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में की गई पूरी एसआईआर प्रक्रिया रद्द की जाए। कानून के



मुताबिक, एसआईआर किसी आपात स्थिति में की जाती है। विधानसभा चुनाव के दौरान 40 से 60 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए और इसके जरिए सत्ता हासिल की गई। अब एसआईआर के जरिए 2 करोड़ लोगों को हटाया जा रहा है। ये 2 करोड़ मतदाता कौन हैं? हमारा

विरोध इस बात को लेकर है कि आप सरकार कैसे चला रहे हैं और सत्ता का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। सरकार कौन बनाएगा और सरकार कैसे चलेगी, इसका फैसला जनता और मतदाताओं को करना चाहिए। इसका फैसला चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए।

भाजपा ने उत्तराखंड से दिनेश आर्य और पश्चिम बंगाल से कोयल मल्लिक को घोषित किया राज्यसभा उम्मीदवार

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर 2026। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तराखंड में होने वाले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव और पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उप-चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है। पार्टी ने उत्तराखंड से दिनेश आर्य और पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक (कोयल मल्लिक) को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की ओर से रविवार को जारी प्रेस विज्ञापन के अनुसार, केंद्रीय चुनाव समिति ने दोनों राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव होगा है। इसके लिए पार्टी ने श्री दिनेश आर्य को उम्मीदवार घोषित किया



है। वहीं, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उप-चुनाव के लिए श्रीमती रुक्मिणी मल्लिक (कोयल मल्लिक) को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दिनेश आर्य उत्तराखंड में राज्यस्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष (दर्जा राज्यमंत्री) रह चुके हैं। वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के



जनसंपर्क अधिकारी, भाजपा के नैनीताल के पूर्व जिलाध्यक्ष और अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं, रुक्मिणी मल्लिक कोयल मल्लिक के नाम से जानी जाती हैं। वह अभिनेत्री और राजनेता हैं तथा मुख्य रूप से बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वह तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रह

चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में एक राज्यसभा सीट रिक्त हुई है। इस सीट से तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रुक्मिणी मल्लिक ने 16 जुलाई को इस्तीफा दिया था। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2032 तक था। रिक्त हुई इसी सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर द्विवार्षिक चुनाव तथा पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव 16 अक्टूबर को कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 11 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है। इसके चलते इन सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराया जा रहा है। उम्मीदवार 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

पिथौरागढ़ में भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नोमैडिक एलिफेंट-2026' संपन्न

पिथौरागढ़, 04 अक्टूबर 2026। भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नोमैडिक एलिफेंट-2026' का 18 वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। 20 सितंबर से तीन अक्टूबर तक चले इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और समझ को बेहतर बनाने के साथ दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण और रक्षा संबंधों को और मजबूत करना था। अभ्यास के दौरान भारत और मंगोलिया की सैन्य टुकड़ियों ने एक साथ प्रशिक्षण लिया और विभिन्न परिचालन परिस्थितियों में संयुक्त रूप से कार्य करने की क्षमता को परखा। दोनों पक्षों ने अपने आप-परेक्षण अनुभव, प्रशिक्षण पद्धतियों और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा किया। इससे संयुक्त वातावरण में काम करने के लिए दोनों



सेनाओं के बीच समन्वय और आपसी समझ को बढ़ाने में मदद मिली। संयुक्त सैन्य अभ्यास को तीन चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में 20 से 23 सितंबर तक 'इटीग्रेसन' के तहत दोनों देशों के सैनिकों ने एक-दूसरे की परिचालन प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण पद्धतियों और कार्यप्रणाली को समझा। इस दौरान दोनों टुकड़ियों के बीच समन्वय

विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। दूसरे चरण में 24 से 30 सितंबर तक संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियां और कॉम्बैट ड्रिल आयोजित की गईं। सैनिकों ने विभिन्न सामरिक परिस्थितियों में संयुक्त रूप से अभ्यास किया और अभियान के दौरान आवश्यक तालमेल को मजबूत किया। अंतिम चरण में एक और दो अक्टूबर को 'वैलिडेशन एक्सरसाइज' आयोजित की गईं। इसमें दोनों देशों के सैनिकों ने पहले चरणों में प्राप्त प्रशिक्षण और कौशल को एकीकृत संयुक्त अभ्यास के माध्यम से परखा। इस चरण का उद्देश्य संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान विकसित परिचालन क्षमताओं का मूल्यांकन करना था। अभ्यास के दौरान दोनों सैन्य टुकड़ियों ने विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लिया।

जनसांख्यिकी और नए आर्थिक क्षेत्रों के चलते भारत के पास विकास की लंबी संभावना : एस जयशंकर

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर 2026। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत के सामने अगले पांच से दस वर्षों में हो नहीं बल्कि आने वाले दशकों में भी उच्च आर्थिक वृद्धि की संभावना है। उन्होंने इसके पीछे देश की जनसांख्यिकी और नई आर्थिक संभावनाओं को महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत के पास औद्योगीकरण के पारंपरिक रास्ते से अलग नए अवसर तलाशने की क्षमता है। विदेश मंत्री ने 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया।



जयशंकर ने इस दौरान भारत की विकास यात्रा, यूरोप के साथ बढ़ती साझेदारी और बदलती वैश्विक व्यवस्था पर भारत का दृष्टिकोण रखा। इसमें उन्होंने भारत के संदर्भ में आने वाले दशकों तक उच्च आर्थिक वृद्धि की संभावना जताई। साथ ही विश्व के अन्य देशों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिए। डॉ. जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका की स्थिति में बढ़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी पसंद के अनुसार खुद को नए

पहल भी देशों के बीच सहयोग के नए स्वरूप को दर्शाती है। जयशंकर ने कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था ने बहुध्रुवीयता के उभार को तेज किया है। बढ़ती परस्पर निर्भरता के कारण देशों के लिए किसी एक खेमे से पूरी तरह अलग रहना संभव नहीं है। ऐसे में वे अपने हितों के अनुसार विभिन्न शक्तियों के साथ संबंध बनाएंगे और जोखिमों को संतुलित करते हुए सहयोग करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि देशों के लिए ऐसे साझेदारों के साथ संबंध बनाना जरूरी होता जा रहा है, जिनके साथ उनके हित हमेशा पूरी तरह मेल नहीं खाते। इसे उन्होंने जोखिम संतुलित करते हुए दूसरी प्रमुख विशेषता चीन का उभार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका-चीन के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिसका असर अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। इस प्रतिस्पर्धा के बीच देशों की आपसी निर्भरता भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसी प्रमुख बहुपक्षीय संस्था में गतिरोध दिखाई दे रहा है। इसके परिणाम स्वरूप छोटे समूहों और सीमित दायरे वाले सहयोग के नए प्रारूप उभर रहे हैं। जयशंकर ने आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को उभरती शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र में प्रभावशाली बनने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना जरूरी नहीं है।



सीईटी परीक्षा में सेंटर तलाशते रहे अभ्यर्थी,गूगल मैप ने बढाई परेशानी

तीन घंटे सफर के बाद भी लोकेशन खोजने में लगा समय,5-10 मिनट की देरी पर केंद्र में प्रवेश के लिए लगानी पड़ी गुहार

सीईटी परीक्षा का सेंटर बना पहली, गूगल मैप ने भी अभ्यर्थियों को भटकाया

परीक्षा देने पहुंचे,पहले सेंटर खोजते रहे...गूगल मैप ने बढ़ाई अभ्यर्थियों को मुश्किल

सीईटी परीक्षा में रास्ता ही बन गया परीक्षा,सेंटर तलाशने में अभ्यर्थियों के घंटे बर्बाद

तीन घंटे का सफर,फिर सेंटर की तलाश...सीईटी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से पहले नई परीक्षा

इतना बड़ा स्कूल,फिर गूगल मैप पर लोकेशन क्यों उलझी? सीईटी अभ्यर्थियों की बढ़ी परेशानी

अंबिकापुर के केशवपुर स्थित स्वामी आत्मानंद विद्यालय बना परीक्षा केंद्र,तीन घंटे सफर के बाद भी लोकेशन तलाशने में उलझे अभ्यर्थी,कुछ मिनट की देरी पर केंद्र के बाहर लगानी पड़ी गुहार

—संवाददाता—
अंबिकापुर,04 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी-2026 का आयोजन 4 अक्टूबर को किया गया, परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र में सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केशवपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों के लिए जहां महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा का दिन महत्वपूर्ण था, वहीं कुछ अभ्यर्थियों के सामने परीक्षा से पहले ही ऐसी परेशानी खड़ी हो गई,जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए गूगल मैप का सहारा लेने वाले कई अभ्यर्थी सेंटर की सही लोकेशन तलाशते-तलाशते परेशान होते रहे,बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह परेशानी और बढ़ी हो

तीन घंटे का सफर,फिर भी खत्म नहीं हुई सेंटर तलाशने की परेशानी...

अभ्यर्थियों के अनुसार वे परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचने के उद्देश्य से काफी पहले अपने घर से निकले थे,लेंबा सफर तय कर वे अंबिकापुर पहुंचे,लेकिन इसके बाद जब उन्होंने मोबाइल में गूगल मैप के जरिए केशवपुर स्थित स्वामी आत्मानंद विद्यालय की लोकेशन तलाशनी शुरू की तो उन्हें अपेक्षित सुविधा नहीं मिली, कोई एक स्थान स्पष्ट रूप से पकड़ में नहीं आने के कारण रास्ता तलाशने में समय लगता गया, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने.फिर लोकेशन जांचने और आसपास के लोगों से पूछने के बीच काफी समय निकल गया, परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के लिए यह केवल रास्ता भटकने का मामला नहीं था,उनके सामने लगातार घड़ी चल रही थी, परीक्षा का निर्धारित समय नजदीक आ रहा था और दूसरी तरफ सेंटर तक पहुंचने का रास्ता ही पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, यही कारण रहा कि कुछ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के आसपास पहुंचने के बाद भी अंदर जाने की प्रक्रिया को लेकर तनाव में नजर आए।

गई, कई अभ्यर्थी काफी दूर से सफर करके अंबिकापुर पहुंचे थे.लेकिन शहर पहुंचने के बाद भी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए आसान नहीं रहा, अभ्यर्थियों की मानें तो उन्हें गूगल पर परीक्षा केंद्र की लोकेशन खोजने में परेशानी हुई, मोबाइल पर लोकेशन तलाशने, रास्ता बदलने और स्थानीय लोगों से पूछताछ करने में काफी समय निकल गया, स्थिति यह हो गई कि करीब तीन घंटे का सफर तय करने के बाद भी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा गया, यह समस्या पहली नजर में भले ही छोटी दिखाई दे, लेकिन जिस अभ्यर्थी के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय निर्धारित हो और कुछ मिनट की देरी भी उसके पूरे साल की मेहनत पर भारी पड़ सकती हो, उसके लिए सेंटर की लोकेशन तलाशने में एक-एक मिनट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

गूगल के भरोसे सेंटर खोजते रहे अभ्यर्थी—आज प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दूसरे शहरों और जिलों से परीक्षा देने पहुंचते थे , उनके लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का सबसे आसान माध्यम मोबाइल और डिजिटल मैप बन चुका है, पहली बार किसी शहर में आने वाला अभ्यर्थी अक्सर आसपास के लोगों को जानता नहीं है, ऐसे में उसके पास परीक्षा केंद्र के नाम और मोबाइल लोकेशन के अलावा बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होता, यही स्थिति सीईटी परीक्षा में भी दिखाई दी, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र खोजने के लिए मोबाइल में गूगल मैप देखते रहे, लेकिन जब

लोकेशन को लेकर ही असमंजस की स्थिति पैदा हो जाए तो परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थी मानसिक दबाव में आ गए.जिस समय अभ्यर्थी को शांत मन से परीक्षा की तैयारी और अपने दस्तावेजों पर ध्यान देना चाहिए था, उस समय वह रास्ता खोजने में उलझा रहा।

सेंटर मिला तो प्रवेश को लेकर खड़ी हो गई दूसरी परेशानी— सबसे गंभीर स्थिति उन अभ्यर्थियों के सामने आई जो काफी मशकत के बाद परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, लेकिन निर्धारित प्रवेश समय से कुछ मिनट पीछे रह गए, अभ्यर्थियों के अनुसार करीब 5 से 10 मिनट की देरी होने पर उन्हें परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात लोगों के सामने अपनी परेशानी बतानी पड़ी, उन्हें यह समझाने की कोशिश करनी पड़ी कि देरी जानबूझकर नहीं हुई बल्कि सेंटर की लोकेशन तलाशने में समय निकल गया, कई अभ्यर्थी के लिए यह स्थिति कितनी तनावपूर्ण रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसने परीक्षा की तैयारी में महीनों लगाए हों, जिसने यात्रा के लिए पहले से समय निकाला हो और जो समय से पहले शहर पहुंच गया हो, उसके सामने यदि केवल सेंटर की लोकेशन के कारण प्रवेश का संकट खड़ा हो जाए तो परेशानी स्वाभाविक है।

मामला सिर्फ गूगल मैप का नहीं, परीक्षा व्यवस्था का भी— इस पूरे मामले को केवल गूगल मैप की समस्या कहकर खत्म करना भी पर्याप्त नहीं होगा, सवाल यह है कि

जब किसी बड़े विद्यालय को राज्य स्तरीय परीक्षा का केंद्र बनाया गया था तो क्या परीक्षा से पहले यह सुनिश्चित किया गया था कि उसकी डिजिटल लोकेशन सही और स्पष्ट रूप से उपलब्ध है या नहीं? क्या परीक्षा केंद्र की लोकेशन को अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जांचा गया था? क्या बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए मुख्य मार्गों पर परीक्षा केंद्र से संबंधित दिशा-सूचक लगाए गए थे? क्या केंद्र तक पहुंचने में परेशानी वाले स्थानों पर कोई सहायता व्यवस्था थी? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर परीक्षा आयोजित करने वाली व्यवस्था को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इतने बड़े विद्यालय का पता डिजिटल मैप पर स्पष्ट क्यों नहीं?—स्वामी आत्मानंद विद्यालय का नाम किसी छोटे निजी भवन की तरह नहीं है, यह एक बड़ा और जाना-पहचाना विद्यालय है,जब ऐसे विद्यालय को राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का वह पहुंचना तय होता है, ऐसे में यदि अभ्यर्थियों को उसके वास्तविक स्थान तक पहुंचने में परेशानी होती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि परीक्षा केंद्र की डिजिटल पहचान और लोकेशन को पहले से क्यों नहीं जांचा गया? यहां अभ्यर्थियों की परेशानी को केवल उनकी व्यक्तिगत समस्या मानना भी उचित नहीं होगा,क्योंकि बाहर से आने वाला हर अभ्यर्थी उस शहर की गलियों और स्थानीय रास्तों से परिचित नहीं होता, वह प्रवेश पत्र पर दिए गए नाम को मोबाइल में डालकर रास्ता तलाशता है और जिस डिजिटल जानकारी पर उसे भरोसा होता है, उसी के आधार पर आगे बढ़ता है।

परीक्षा केंद्र की जानकारी सिर्फ प्रवेश पत्र में देना पर्याप्त नहीं— परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में केंद्र का नाम और पता दिया जाता है,लेकिन आज के डिजिटल दौर में केवल कागज पर पता लिख देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता,विशेषकर जब परीक्षा केंद्र किसी दूसरे शहर या क्षेत्र में हो, तब आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा केंद्र की सटीक डिजिटल लोकेशन उपलब्ध हो, गूगल मैप या अन्य मैपिंग प्लेटफॉर्म पर नाम और स्थान स्पष्ट दिखाई दे, परीक्षा से पहले

अभ्यर्थियों को लोकेशन जांचने की सलाह के साथ सही डिजिटल लिंक दिया जाए.प्रमुख मार्गों पर परीक्षा केंद्र के दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएं,बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरत पड़ने पर हेल्प डेस्क या मार्गदर्शन व्यवस्था हो, परीक्षा केंद्र के आसपास पर्याप्त संकेतक लगाए जाएं, ताकि अभ्यर्थी अंतिम समय में रास्ता न भटकें।

परीक्षा के दिन कुछ मिनट की देरी भी भारी पड़ सकती है— प्रतियोगी परीक्षा में समय का महत्व किसी से छिपा नहीं है,अभ्यर्थी महीनों तक पढ़ाई करता है, आवेदन करता है, परीक्षा शुल्क जमा करता है, यात्रा की तैयारी करता है और परीक्षा के दिन निर्धारित समय से पहले निकलता है, ऐसे में अगर परीक्षा केंद्र खोजने में ही एक-दो घंटे निकल जाएं तो अभ्यर्थी की मानसिक स्थिति पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थी को परीक्षा में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना है, न कि परीक्षा केंद्र खोजने की परीक्षा देनी है, यदि कोई अभ्यर्थी रास्ते की समस्या के कारण देर से पहुंचता है तो उसके लिए यह केवल 5 या 10 मिनट की देरी नहीं होती, उसके पीछे महीनों की तैयारी और आर्थिक खर्च जुड़ा होता है।

सरकार और परीक्षा एजेंसी को भी सोचना होगा—इस मामले से छत्तीसगढ़ सरकार और परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारियों के सामने एक व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है, डिजिटल युग में जब हर जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराने की बात होती है, तब एक परीक्षा केंद्र की सटीक लोकेशन उपलब्ध कराना भी व्यवस्था का हिस्सा क्यों न हो? अगर किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र खोजने में परेशानी होती है तो इसकी जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी पर डालना भी उचित नहीं होगा,अभ्यर्थी को यह कहा जा सकता है कि वह एक दिन पहले सेंटर देख ले, लेकिन यदि डिजिटल मैप पर ही लोकेशन स्पष्ट नहीं है तो एक दिन पहले जाकर सेंटर तलाशना भी हर अभ्यर्थी के लिए संभव नहीं है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो दूरदराज के क्षेत्रों से आते हैं और परीक्षा के दिन ही शहर पहुंचते हैं।

एक छोटी तकनीकी कमी,लेकिन अभ्यर्थी के लिए बड़ा नुकसान-देखने में

यह समस्या बहुत सामान्य लग सकती है—गूगल मैप पर लोकेशन नहीं मिली और कुछ देर रास्ता खोजने में लग गई, लेकिन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की नजर से देखा जाए तो यही छोटी तकनीकी कमी उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, एक अभ्यर्थी तीन घंटे यात्रा करके परीक्षा केंद्र वाले शहर में पहुंचता है, इसके बाद भी यदि उसे सेंटर तलाशने में अतिरिक्त समय देना पड़े, फिर 5-10 मिनट की देरी के कारण उसे केंद्र के बाहर अपनी स्थिति समझानी पड़े, तो उसकी पूरी परीक्षा व्यवस्था तनाव में बदल जाती है, मामला केवल गूगल मैप का नहीं है, मामला उस व्यवस्था का है जिसमें एक अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए घर से निकलने के बाद परीक्षा केंद्र तक बिना किसी भ्रम और परेशानी के पहुंचना चाहिए।

अब जिम्मेदारों को करना चाहिए समीक्षा—इस पूरे मामले से परीक्षा व्यवस्था के सामने एक सीख भी निकलती है,भविष्य में किसी भी बड़े प्रतियोगी या पात्रता परीक्षा के लिए केंद्र तय करने के साथ-साथ उसकी ग्राउंड और डिजिटल दोनों स्तरों पर पहुंच की जांच की जानी चाहिए, परीक्षा केंद्र का नाम सही है या नहीं,पता सही है या नहीं, मोबाइल मैप पर लोकेशन सही है या नहीं, मुख्य सड़क से वहां पहुंचने का रास्ता स्पष्ट है या नहीं—इन सभी चीजों की जांच परीक्षा से पहले होनी चाहिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले केंद्र का पता उपलब्ध कराना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि वह पता उन्हें वास्तव में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए, सवाल जो अब उठना जरूरी है, जब इतने बड़े विद्यालय को सीईटी-2026 जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का केंद्र बनाया गया, तो क्या परीक्षा से पहले उसकी डिजिटल लोकेशन की जांच की गई थी? अगर जांच की गई थी तो अभ्यर्थियों को सेंटर तलाशने में इतनी परेशानी क्यों हुई? और अगर जांच नहीं की गई थी तो इतनी बड़ी परीक्षा के केंद्र निर्धारण में इस बुनियादी व्यवस्था को नजरअंदाज क्यों किया नहीं है, अभ्यर्थियों की परेशानी को केवल 'रास्ता नहीं मिला' कहकर खत्म नहीं किया जा सकता, यह डिजिटल दौर में परीक्षा केंद्रों की तैयारी, सूचना व्यवस्था और अभ्यर्थी सुविधा की समीक्षा का विषय है।

जमीन बिक्री के पैसों को लेकर पिता की हत्या,आरोपी पुत्र गिरफ्तार

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,04 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

जमीन बिक्री से मिले पैसों को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में एक पुत्र ने अपने पिता के सिर पर टांगी से वार कर उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही दरिमा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त खून लगी लोहे की टांगी भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार ग्राम भालुकछार इमलीपारा निवासी मधुवन शंकर सिंह ने 3 अक्टूबर को थाना दरिमा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह करीब 11 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनके बड़े भाई रामाशंकर सिंह की उनके ही पुत्र मुकेश कुमार सिंह ने टांगी मारकर हत्या कर दी है। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो रामाशंकर का शव घर के कमरे में पड़ा मिलता। उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और काफी खून निकला हुआ था। प्राथी की रिपोर्ट पर थाना दरिमा में अपराध क्रमांक 225/2026 के तहत धारा 103(1) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एफएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने पुलिस टीम को तत्काल कार्रवाई कर आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। निर्देश के बाद थाना दरिमा पुलिस एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक के पुत्र मुकेश कुमार सिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम भालुकछार, थाना दरिमा, को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने जमीन बिक्री के पैसों को लेकर पिता से विवाद होने और गुरसे में टांगी से उनके सिर पर वार करने की बात स्वीकार की। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त खून लगी लोहे की टांगी जब्त की। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।



चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए इंडिया गठबंधन 8 को निकालेगा लोकतंत्र बचाओ मार्च घड़ी चौक से शुरू होगी रैली,गांधी चौक पर सविधान के अनुच्छेद 326 का होगा पाठ...राष्ट्रपति के नाम सौपेंगे ज्ञापन

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,04 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरगुजा में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने 'लोकतंत्र बचाओ' आंदोलन को लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। 30 सितंबर को नई दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में लिए गए निर्णयों के परिपालन में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस, सीपीएम और सीपीआई के नेताओं की संयुक्त बैठक हुई। बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में 8 अक्टूबर को जिला स्तरीय संयुक्त रैली निकालने का ऐलान किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने बताया कि सरगुजा में कांग्रेस के साथ सीपीआई और सीपीएम सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेंगे। गठबंधन के घटक दलों के साथ चर्चा के बाद संयुक्त कार्यक्रम तय किया गया है। उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर को रैली घड़ी चौक से आमसभा के रूप में शुरू होगी।

चुनाव आयोग भाजपा की सुविधा के अनुसार काम कर रहा : प्रेसवार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा की सुविधा के अनुसार चुनाव आयोग का संचालन कर रहे हैं और अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को



इसके बाद रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंचेगी। यहां सविधान के अनुच्छेद 326 का सार्वजनिक पाठ किया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन समाप्त किया जाएगा। रैली की तैयारियों को लेकर ब्लॉक स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी।

चुनाव आयोग भाजपा की सुविधा के अनुसार काम कर रहा : प्रेसवार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा की सुविधा के अनुसार चुनाव आयोग का संचालन कर रहे हैं और अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को

नजरअंदाज किया जा रहा है। भगत ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रवैये के खिलाफ शेष दो चुनाव आयुक्तों ने कई बार डिसेंट नोट दिया है। उनका आरोप था कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में भी पक्षपात किया जा रहा है और इसी वजह से चुनाव व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भगत ने कहा कि भाजपा के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी के बावजूद उसके सत्ता में बने रहने के पीछे आयोग की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, ये सभी आरोप राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए हैं और इन पर चुनाव आयोग या संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सफेद कपड़े ने बढ़ाया संदेह,छह फीट खुदाई के बाद भी नहीं मिला कुछ सेमीघोघरा जंगल में गड्ढे को लेकर ग्रामीणों में मची थी हलचल,बोलेरो सवार दो युवकों के फावड़ा लेकर पहुंचने की सूचना पर पुलिस ने रातभर की निगरानी...

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,04 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

उदयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सानीबरां के सेमीघोघरा जंगल में एक ताजा गड्ढे को लेकर शनिवार से ग्रामीणों के बीच बनी संशय की स्थिति रविवार को खुदाई के बाद खत्म हो गई। करीब छह फीट तक गड्ढा

खोदने के बाद भी उसमें से कोई सदिध वस्तु या अन्य सामग्री नहीं मिली। गड्ढे से बाहर निकले सफेद कपड़े के कारण ग्रामीणों में तरह-तरह की आशंकाएं बनी हुई थीं। जानकारी के अनुसार, बुधवार को कुछ ग्रामीण जंगल में मवेशी चराने गए थे। इसी दौरान उन्होंने सफेद रंग की बोलेरो को जंगल में आते देखा। ग्रामीणों के अनुसार,

वाहन से दो युवक फावड़ा लेकर उतरे और जमीन खोदने के बाद वहां से चले गए। शुरुआत में ग्रामीणों ने इसे छूही मिट्टी निकालने से जोड़कर देखा, लेकिन बाद में गड्ढे के पास पहुंचे तो वहां मिट्टी भारी हुई थी और सफेद कपड़े का एक हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा था। इसके बाद ग्रामीणों ने मामले को जानकारी गांव में दी। सूचना

मिलने के बाद शनिवार को उदयपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी गड्ढे और बाहर दिखाई दे रहे कपड़े को देखा। अंधेरा होने के कारण तत्काल खुदाई नहीं कराई गई। किसी तरह की डेडबॉडी न हो, इसलिए पुलिस ने रातभर मौके पर निगरानी रखी। रविवार को तहसीलदार तारा सिदार की मौजूदगी में गड्ढे की खुदाई शुरू कराई गई।



वडनगर से वाराणसी तक संकल्प की यात्रा,कोरिया में उमड़ी युवा शक्ति बाइक यात्रा के साथ सेवा का संदेश,कोरिया में जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत

प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की मौजूदगी ने बढ़ाया उत्साह,सैकड़ों बाइकर्स के साथ जगह-जगह उमड़ी युवा शक्ति



-संवाददाता-
बैकुण्ठपुर 04 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक निकली 'जल-जन सेवा संकल्प बाइक यात्रा' के कोरिया जिले में प्रवेश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों ने जगह-जगह भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया, सैकड़ों युवाओं की बाइक रैली, पारंपरिक लोकनृत्य, पुष्पवर्षा और जनभागीदारी से यात्रा का स्वागत पूरे जिले में उत्सव जैसा नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों की जनसेवा को समर्पित यह यात्रा सेवा, जल संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, जनजागरूकता और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का संदेश लेकर वडनगर से वाराणसी की ओर बढ़ रही है, यात्रा में शामिल युवा बाइकर्स विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर सेवा, सामाजिक सरोकार और जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता का संदेश दे रहे हैं।

मनैन्द्रगढ़ से बाइकर्स के साथ कोरिया पहुंची यात्रा- कोरिया जिले की सीमा में यात्रा के प्रवेश के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बाइकर्स के साथ पहुंचे, उनके साथ एससीबी भाजपा जिलाध्यक्ष चंचा देवी पावले भी मौजूद रहीं, वहीं कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम पूरे प्रवास के दौरान सेवा संकल्प अभियान से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से उपस्थित रहे, जिले की सीमा में यात्रा के प्रवेश पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष सतेंद्र राजवाड़े

सैकड़ों मोटरसाइकिलों के साथ उमड़ी युवा शक्ति

भाजयुमो जिलाध्यक्ष सतेंद्र राजवाड़े के समन्वय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सैकड़ों मोटरसाइकिलों के साथ यात्रा के स्वागत में पहुंचे। भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष राकेश खाखा, रमेश तिवारी, जिला महामंत्री कमलेश साहू, साक्षी सिंह, जिला मंत्री पी.एस. सिंह, परवेन्द्र सिंह, शिवपुर चर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीराम दुबे, बैकुण्ठपुर मंडल अध्यक्ष विकास दुबे, पटना मंडल अध्यक्ष जय राजवाड़े, कुडेली मंडल अध्यक्ष मनोज यादव, सोनहत मंडल अध्यक्ष दिलीप राजवाड़े सहित युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की।

कर्मा नृत्य ने बढ़ाई आयोजन की रौनक

यात्रा के स्वागत में स्थानीय पारंपरिक कर्मा नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक अंदाज में बाइकर्स का अभिनंदन किया, इस दौरान उत्साह और बढ़ गया जब प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी बाइकर्स के साथ लोकनृत्य में शामिल हुए, जनप्रतिनिधियों, युवाओं और बाइकर्स की सामूहिक सहभागिता ने स्वागत कार्यक्रम को आत्मीय और यादगार बना दिया।

के नेतृत्व में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बाइकर्स और अतिथियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, इसके बाद नगर आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्ण बिहारी जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, जिला महामंत्री पंकज गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष रविशंकर राजवाड़े, बसंत राय, जिला कोषाध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा, जिला मंत्री शारदा गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी तीर्थ राजवाड़े, मंडल अध्यक्ष मैनेजर राजवाड़े, संजय चिकनसूरी, रोशन राजवाड़े, गोकर्ण शुक्ला, गोपाल राजवाड़े, आनंद राजवाड़े, धर्मवती राजवाड़े, रीता यादव,

संगीता गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने यात्रा का स्वागत किया। **चर्चा में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण-**यात्रा के शिवपुर-चर्चा पहुंचने पर मंडल अध्यक्ष दीपा विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष अरुण जायसवाल, जिला मंत्री प्रदीप तिवारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने बाइकर्स का स्वागत किया, यहां यात्रा में शामिल बाइकर्स ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

खरवत तिराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत-यात्रा के खरवत तिराह

पहुंचने पर ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष कृष्णा प्रजापति, महामंत्री अहिल्या राजवाड़े, सुरेंद्र कुमार, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवचरण साहू, महामंत्री प्रेमप्रकाश पांडे, जय चक्रधारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल खटिक, जनपद अध्यक्ष सोनहत आशा देवी सोनपाकर, मंडल अध्यक्ष राजाराम राजवाड़े, जिला पंचायत सदस्य शिवकुमारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया, यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, युवाओं का काफिला भी बढ़ता गया, रास्ते में विभिन्न स्थानों पर नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने बाइकर्स का अभिनंदन किया।

पटना में पूजा-अर्चना के साथ युवाओं से संवाद-पटना पहुंचने पर गायत्री मंदिर में पूजा-अर्चना की गई, इसके बाद बाइकर्स के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, यहां प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने युवाओं से संवाद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों की जनसेवा तथा सेवा संकल्प अभियान के उद्देश्यों को लेकर अपने विचार रखे, इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह, जिला पंचायत सदस्य गीता राजवाड़े, जिला महामंत्री कपिल जायसवाल, जवाहर गुप्ता, रविशंकर शर्मा, वर्षा साहू, सुनीता कुंरे, सुनील सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामलखन यादव, मंडल महामंत्री सच्चिदानंद द्विवेदी, सत्यम साहू, योगेंद्र मिश्रा, रूपचंद गुप्ता, दिनेश चक्रधारी, भाजयुमो के रिशेरा सिंह सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं गायत्री परिवार के सदस्यों ने बाइकर्स का स्वागत किया।

युवाओं की ऊर्जा को सेवा और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने वाला अभियान:रामविचार-प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा की वडनगर से वाराणसी तक निकली जल-जन सेवा संकल्प यात्रा सेवा, जल संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और जनभागीदारी का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है, कोरिया जिले में जिस तरह युवाओं, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने यात्रा का स्वागत किया है, वह जनभागीदारी की भवना को दर्शाता है, युवाओं की ऊर्जा को सेवा और सामाजिक सरोकारों से जोड़ना इस तरह के अभियानों की महत्वपूर्ण दिशा है, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता आवश्यक है, कोरिया में यात्रा को मिले इस उत्साह से सेवा संकल्प के संदेश को और व्यापक रूप से आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली है।

इस यात्रा का उद्देश्य केवल बाइक से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना नहीं, जनजागरूकता के संकल्प को आगे बढ़ाना है: श्याम बिहारी-स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा की जल-जन सेवा संकल्प यात्रा सेवा, सामाजिक सहभागिता और युवाओं की सक्रिय भूमिका का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है, कोरिया जिले में प्रवेश से लेकर विभिन्न पड़वों तक जिस उत्साह के साथ युवाओं और नागरिकों ने बाइकर्स का स्वागत किया, वह इस अभियान के प्रति जनभागीदारी को दर्शाता है, सेवा, पर्यावरण संरक्षण, जल

संरक्षण और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों को लेकर युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, इस यात्रा का उद्देश्य केवल बाइक से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते में समाज से संवाद करना और सेवा एवं जनजागरूकता के संकल्प को आगे बढ़ाना है, कोरिया की जनता और युवाओं ने जिस आत्मीयता से यात्रा का स्वागत किया, उसके लिए सभी का आभार है।

युवा शक्ति बनी

यात्रा की सबसे बड़ी पहचान

पूरी यात्रा के दौरान भाजपा के विभिन्न मोर्चा-प्रकोटों के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष-महामंत्री, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए, सैकड़ों मोटरसाइकिलों के साथ युवाओं की मौजूदगी ने यात्रा को अलग पहचान दी, वडनगर से वाराणसी की ओर बढ़ रही इस यात्रा के कोरिया पहुंचने पर सेवा, जल संरक्षण, पर्यावरण चेतना, सामाजिक सहभागिता और युवा शक्ति का संदेश प्रमुखता से सामने आया। जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुए स्वागत कार्यक्रमों में स्थानीय परंपरा और जनभागीदारी का भी समावेश देखने को मिला, कर्मा नृत्य से लेकर बाइक रैली तक और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण से लेकर पटना में युवाओं के संवाद तक-यात्रा का कोरिया प्रवास विभिन्न सामाजिक एवं जनभागीदारी गतिविधियों से जुड़ा रहा।

तीज की ऑनलाइन प्रतियोगिता में भी दिखा महिलाओं का उत्साह

समभाव महिला मंच ने घोषित किए परिणाम, मुक्त गुप्ता प्रथम, गायत्री सिन्हा द्वितीय और श्रद्धा सोनी तृतीय



-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 04 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

तीज के रंग, परंपरा और महिलाओं के उत्साह को डिजिटल मंच पर भी जीवंत रखने की पहल समभाव महिला मंच ने की। मंच की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन तीज उत्सव प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। इसमें महिलाओं ने तीज के पारंपरिक स्वरूप, श्रृंगार और उत्सव से जुड़े अपने अंदाज को ऑनलाइन साझा किया। प्रतियोगिता में मुक्त गुप्ता ने प्रथम, गायत्री सिन्हा ने द्वितीय और श्रद्धा सोनी ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं रेखा इंगोले और संगीता सोनी को विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया। तीज केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए मिलन, उत्साह और अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर भी माना जाता है। छत्तीसगढ़ में तीजा-पोरा की परंपरा में महिलाओं की भागीदारी के साथ पारंपरिक गीत, झूलें और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां भी उत्सव का हिस्सा रहती हैं। इसी भाव को आधुनिक माध्यम से जोड़ते हुए समभाव महिला मंच ने ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में अलग-अलग समाज की महिलाओं की सहभागिता रही। मंच का उद्देश्य विभिन्न समाजों की महिलाओं को एक साझा मंच पर जोड़ना और आपसी मेल-जोल, सौहार्द एवं सहभागिता को बढ़ावा देना है। तीज के दौरान सोलह श्रृंगार, मेहंदी, पारंपरिक परिधान और शिव-पार्वती की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में हस्तालिका तीज को माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव से उनके विवाह से जुड़ा पर्व माना गया है।

टाई ब्रेकर में अडची ने राता को 7-6 से हराया, पोड़ीपा की 2-1 से जीत

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 04 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

गांधी स्टेडियम में चल रही संभाव स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के तहत रविवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में एफसी राता और करिया क्लब अडची के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। निर्धारित समय तक दोनों टीमों गोल नहीं कर सकीं। इसके बाद टाई ब्रेकर में अडची ने 7-6 से जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बनाई। दूसरे मुकाबले में जेएमसी अम्बिकापुर और एफसी पोड़ीपा आमने-सामने रहे। पहले हाफ में पोड़ीपा ने शानदार खेल दिखाते हुए दो गोल कर 2-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में जेएमसी अम्बिकापुर ने वापसी की कोशिश की। टीम ने अंतिम समय में एक गोल कर अंतर कम किया, लेकिन बराबरी नहीं कर सकी। पोड़ीपा ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता में 5 अक्टूबर को पहला मैच एसबी क्लब धंवरपुर और न्यू स्टार क्लब कोटया के बीच खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले में एफसी गुमगरा का सामना एफसी लवईडीह से होगा।



49 दिन में 2.74 लाख लोगों तक पहुंचा सरगुजा पुलिस का साइबर सुरक्षा संदेश 8,227 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, साइबर जागरूकता में सरगुजा रेंज में अव्वल...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 04 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल ठगी के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए गए 'साइबर जागृति अभियान' में सरगुजा पुलिस ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में 49 दिनों तक चले अभियान के दौरान सरगुजा जिले में 8,227 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस ने जिले के करीब 2 लाख 74 हजार 247 नागरिकों तक सीधे पहुंचकर साइबर सुरक्षा और डिजिटल सतर्कता का संदेश दिया। अभियान के प्रदर्शन के आधार पर सरगुजा पुलिस ने पूरे सरगुजा रेंज के जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए साइबर जागरूकता के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया। अभियान के दौरान पुलिस की विशेष टीमों ने शहरों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक



पहुंच बनाई। स्कूल, कॉलेज, हाट-बाजार, शासकीय कार्यालय, पंचायत भवन और सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को साइबर अपराध के बदलते तौर-तरीकों की जानकारी दी गई। अभियान का उद्देश्य केवल लोगों को जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें इतना जागरूक और सक्षम बनाना रहा कि वे स्वयं साइबर ठगी से बच सकें और अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को

भी इसके प्रति सतर्क कर सकें। रक्षाबंधन पर्व के दौरान 'साइबर रक्षा सूत्र' अभियान के जरिए पुलिस ने जागरूकता को उत्सव से जोड़ा। पुलिस टीमों ने नागरिकों और महिलाओं की कलाई पर साइबर सुरक्षा संदेशों से युक्त राखी बांधकर उन्हें डिजिटल ठगी से बचने का संकल्प दिलाया। इसी तरह जमाफाटमी के अवसर पर आयोजित 'मटका फोड़' कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों के

बीच साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता का संदेश पहुंचाया गया। इन अभिनव गतिविधियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और साइबर सुरक्षा को लेकर संवाद को व्यापक बनाया। अभियान के तहत विद्यार्थियों और युवाओं को सोशल मीडिया हैकिंग, गेमिंग फ्रॉड और ऑनलाइन बुलिंग से बचाव के तरीके बताए गए। वरिष्ठ नागरिकों एवं गृहिणियों को डिजिटल बैंकिंग के दौरान OTP, UPI PIN, बैंक पासवर्ड तथा कार्ड संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 'साइबर ग्राम चौपाल' के माध्यम से ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों की जानकारी दी गई। पुलिस ने KYC अपडेट के नाम पर होने वाली ठगी, शेयर मार्केट एवं ट्रेडिंग फ्रॉड, जीब फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट और फर्जी सांशल मीडिया प्रोफाइल जैसे साइबर अपराधों के संबंध में भी लोगों को विस्तार से जानकारी दी। पुलिस टीमों ने नागरिकों को समझाया कि साइबर अपराधी लगातार ठगी के नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए

किसी भी अनजान कॉल, संदेश, लिंक या ऑनलाइन ऑफर पर तत्काल भरोसा नहीं करना चाहिए। सरगुजा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कभी भी अपना OTP, UPI PIN, बैंक पासवर्ड या कार्ड संबंधी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तो समय में गंवाए बिना तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस के अनुसार साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती समय में शिकायत करने से ठगी की रकम को रोकने की संभावना बढ़ जाती है। सरगुजा पुलिस का कहना है कि साइबर जागृति अभियान को निरंतर जनजागरूकता के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक नागरिक डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सतर्क रह सकें।

करमा खेलने के दौरान विवाद, रात में गैरेज पहुंचे युवकों ने युवक की हत्या की

खेरबार में वारदात के बाद दो युवक हिरासत में, मृतक गैरेज में करता था काम, हत्या की वजह तलाश रही पुलिस

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 04 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

खेरबार में करमा खेलने के दौरान हुए विवाद के बाद शनिवार देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। विवाद के कुछ देर बाद दो युवक कथित तौर पर कुल्हाड़ी लेकर उसके कमरे में पहुंचे और मारपीट के दौरान उसकी गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। मृतक विश्वजीत कुल्हाड़े उर्फ राजा (27) कोरिया जिले के पटना का निवासी था। वह करीब एक वर्ष से अम्बिकापुर में मायापुर निवासी रमेश सोनी के साथ गैरेज में काम कर रहा था। थाना चौक के पास संचालित गैरेज को कुछ दिन पहले नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के कारण हटा दिया था। इसके बाद करेश सोनी ने खेरबार में गैरेज शुरू किया था। विश्वजीत भी वहीं काम करता था और गैरेज के पास बने कमरे में रहता था। शनिवार रात विश्वजीत, खेरबार निवासी आकाश उर्फ चिंदू,



आकाश और शनि के साथ गांव में करमा खेलने गया था। इस दौरान किसी बात को लेकर चारों के बीच विवाद हो गया और मारपीट भी हुई। इसके बाद विश्वजीत और शनि वापस गैरेज लौट आए। विश्वजीत अपने कमरे में चला गया। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद आकाश उर्फ चिंदू और आकाश कुल्हाड़े लेकर उसके कमरे में पहुंचे। वहां दोनों ने विश्वजीत के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों युवक वहां से फरार हो गए। घटना के बाद शनि ने गैरेज संचालक रमेश सोनी को इसकी जानकारी दी। रविवार सुबह मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।



बातचीत तू-तु-मैं-तु-मैं तक पहुंच गई। भाजपा नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए सवाल किए। इससे कोतवाली परिसर में कुछ देर तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही।

सोशल मीडिया पोस्ट को बताया जा रहा विवाद की वजह: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आकांक्षा टोप्पो किसी मामले को लेकर भाजपा सरगुजा जिला पदाधिकारी धीरज सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद धीरज सिंह के समर्थकों द्वारा भी सोशल मीडिया पर आकांक्षा

टोप्पो के खिलाफ पोस्ट किए जाने की जानकारी है। इसी विवाद के बीच रविवार को दोनों का होटल के पास आमना-सामना हुआ। बताया जाता है कि आकांक्षा टोप्पो द्वारा पूर्व में भी राजनीतिक नेताओं और अन्य लोगों को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की जाती रही हैं और इसे लेकर शिकायतें भी थाने तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि, इन शिकायतों और रविवार को हुए विवाद की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल दोनों पक्षों से पूछताछ और मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।



दो साल पुराने जघन्य हत्याकांड में चार आरोपी दोषी करार...अब सजा का इंतजार,शहर में उठ रही मांग...‘ऐसे अपराध में फांसी से कम सजा नहीं’

8 अक्टूबर को खुलेगा सजा का पन्ना...सूरजपुर डबल मर्डर में चार दोषी,शहर की निगाहें अदालत पर...

सूरजपुर डबल मर्डर : चार दोषी करार, अब 8 अक्टूबर को सजा का फैसला...

दो साल बाद आएगा फैसला, अब 8 अक्टूबर को सजा का इंतजार

मां-बेटी हत्याकांड में मामले चार दोषी करार,अब सजा पर सबकी नजर

दो साल पुराना जखम फिर कुदेगा 8 अक्टूबर का फैसला

मां-बेटी हत्याकांड में चार दोषी,अब सजा कितनी?

अदालत ने दोषी माना,अब 8 अक्टूबर को सजा का ऐलान

सूरजपुर के बहुचर्चित डबल मर्डर में चार दोषी,सजा का काउंटडाउन शुरू

—संवाददाता—

सूरजपुर,04 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। दो साल पहले 13 अक्टूबर 2024 की वह रात सूरजपुर के लिए सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं थी,बल्कि ऐसी भयावह घटना थी जिसने पूरे शहर को भीतर तक हिला दिया था.एक पुलिसकर्मी के घर में घुसकर उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या ने लोगों को झकझोर दिया था,घटना के बाद जिस तरह आक्रोश सड़कों पर उतरा, जिस तरह पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठे और जिस तरह इस मामले की जांच से लेकर न्यायालयीन सुनवाई तक पूरे जिले की नजर बनी रही,उसने इसे सूरजपुर के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल कर दिया। अब उस मामले में 8 अक्टूबर 2026 की तारीख सामने है,चार आरोपी न्यायालय से दोषी करार दिए जा चुके हैं और अब सजा का ऐलान होना बाकी है,जैसे-जैसे 8 अक्टूबर करीब आ रहा है,सूरजपुर में एक ही सवाल चर्चा का विषय बनता जा रहा है,आखिर अदालत दोषियों को क्या सजा सुनाएगी? शहर के एक वर्ग की स्पष्ट मांग है कि जिस तरह की वारदात हुई,उसमें फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए,वहीं न्यायालय के सामने सवाल जनभावना का नहीं, बल्कि कानून, साक्ष्य,अपराध की परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों का है, इसलिए 8 अक्टूबर को अदालत का आदेश ही यह तय करेगा कि इस मामले में दोषियों के लिए सजा की अंतिम तस्वीर क्या होगी।

पुलिस कार्रवाई के बाद बढ़ा टकराव, हमले की साजिश के पीछे पुरानी कार्रवाई थी मुख्य वजह?

घटना के बाद कुलदीप से जुड़े लोगों की ओर से पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए गए और एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास हुआ,जिसमें पुलिस की कार्रवाई को ही सबलों के घेरे में रखा गया,लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दूसरे पक्ष में कुलदीप और उसके परिवार से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस की पूर्व की कार्रवाइयों का सिलसिला भी महत्वपूर्ण रहा,कुलदीप का जिला बदर,उसके चाचा का जिला बदर और दोनों के खिलाफ जिला बदर आदेश के उल्लंघन पर एफआईआर कर जेल भेजे जाने की कार्रवाई, इसके बाद कुलदीप के पिता अशोक साहू का जिला बदर तथा उसके भाई संदीप साहू के खिलाफ एफआईआर और तत्काल गिरफ्तारी—ये ये घटनाक्रम थे,जिनके बीच पुलिस और कुलदीप पक्ष के बीच टकराव बढ़ता गया,इसी क्रम में पूर्व में चोरी के मामले में प्रधान आरक्षक द्वारा कुलदीप के पिता अशोक साहू के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी उल्लेख सामने आता है,पुलिस की इन लगातार कार्रवाइयों के चलते कुलदीप और उससे जुड़े लोगों की कथित अवैध गतिविधियों पर शकंजा करने की स्थिति बनी,इसी पृष्ठभूमि में पुलिस पर हमले की योजना बनाए जाने की बात सामने आई,कुलदीप के साथ देने वाले चंद्रकांत चौधरी के संबंध में भी यह तथ्य सामने आया कि घटना से कुछ दिन पहले उसे सूरजपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के शोषण से जुड़े मामले में जेल भेजा गया था,घटना के बाद इन घटनाक्रमों को सामने रखने के बजाय पुलिस के खिलाफ एकतरफा माहौल बनाने और आरोपियों के पक्ष में महामंडाइन किए जाने के आरोप लगे, हालांकि,कुलदीप या उसके परिवार की ओर से लगाए गए पुलिस संबंधी आरोपों की पुष्टि इस सामग्री में स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं

ये चार आरोपी जिन्हें 8 अक्टूबर को मिलेगी सजा



दो साल बाद भी वह रात लोगों के जेहन में जिंदा-13 अक्टूबर 2024 की रात को याद करना आज भी सूरजपुर के लोगों के लिए आसान नहीं है,प्रधान आरक्षक के घर में घुसकर उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या कर दी गई थी,घटना के बाद दोनों शवों को घर से दूर ले जाकर वीराने में फेंके जाने की जानकारी सामने आई थी,वारदात की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना के बाद पूरा शहर आक्रोशित हो उठा था,पुलिस परिवार को निशाना बनाए जाने ने लोगों को और अधिक विचलित किया,महिलाओं के बीच इस घटना को लेकर भय का असर लंबे समय तक रहा,लोगों के लिए यह सवाल भी महत्वपूर्ण था कि यदि पुलिस परिवार का घर सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर कितना निश्चित रह सकता है? यही कारण है कि दो साल गुजर जाने के बाद भी इस मामले की चर्चा होती ही उस रात की घटनाएं लोगों के सामने फिर जीवित हो उठती हैं।

घटना से पहले शुरू हुआ घटनाक्रम धीरे-धीरे खूनी वारदात तक पहुंचा—आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई पूर्व सामग्री के अनुसार,घटना से पहले जंगराता कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ था,इसके बाद मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के भाई को पुलिस द्वारा उठाए जाने की बात सामने आई थी,इसके बाद कथित रंजिश बढ़ती गई,13 अक्टूबर को शाम घटनाक्रम ने गंभीर रूप ले लिया। पहले एक आरक्षक पर खौलता तेल फेंके जाने की घटना सामने आई,इसके बाद पुलिस टीम को वाहन से कुचलने का प्रयास किया गया और आरोपी के तलवार लेकर भागने की बात सामने आई,और फिर उसी रात वह घटना हुई जिसने पूरे सूरजपुर को हिला दिया, एक पुलिसकर्मी के परिवार की दो सदस्यों की हत्या,यह घटनाक्रम बताता है कि मामला अचानक हुई एक सामान्य आपराधिक घटना नहीं था, बल्कि उस रात कई घटनाएं एक के बाद एक सामने आई और अंततः दोहरी हत्या पर जाकर उधरी।

वारदात के बाद सड़कों पर उतर आया था आक्रोश

घटना के बाद सूरजपुर में जिस तरह का आक्रोश दिखाई दिया,वह भी इस मामले का महत्वपूर्ण अंग है, लोग सड़कों पर आए,विरोध हुआ, चक्काजाम हुआ,आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी,स्थिति ऐसी बनी कि प्रशासन को कानून-व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़े, घटना के बाद पुलिस प्रशासन में भी बदलाव हुआ और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को हटाए जाने की कार्रवाई हुई,उस समय लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इस घटना के दोषियों को कानून के तहत ऐसी सजा मिलेगी,जो पीड़ित परिवार को न्याय का अहसास करा सके? दो साल बाद वही

विवेचना की भी होगी अग्निपरीक्षा

इस मामले में यदि दोषसिद्धि तक बात पहुंची है इस मामले की दो विवेचना अधिकारी थे निरीक्षक व तत्कालीन कोतवाली पुलिस प्रभारी सूरजपुर विमलेश दुबे जिन्होंने सभी साक्ष्य जुटाए थे,तो इसके पीछे पुलिस की विवेचना,अभियोजन को पैरवी,गवाहों के बयान और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी,अब सजा के स्तर पर भी यह मामला विवेचना और अभियोजन की मजबूती के संदर्भ में देखा जाएगा, यदि न्यायालय अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कठोरतरम सजा देता है, तो इसे मामले की विवेचना और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रभावशीलता के संदर्भ में भी देखा जाएगा, वहीं यदि न्यायालय कोई दूसरी सजा निर्धारित करता है, तो उसका आधार भी न्यायालय के विस्तृत आदेश से ही स्पष्ट होगा,इसलिए अभी से सजा को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, 8 अक्टूबर का न्यायिक आदेश ही बताएगा कि अदालत ने पूरे मामले को किस दृष्टि से देखा।

सरकार और पुलिस मुख्यालय ने माना था चुनौतीपूर्ण मामला

इस मामले की जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ शासन तथा पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार निगरानी रही,वर्तमान आईजी दीपक झा तथा पूर्व एवं वर्तमान एसपी क्रमशः प्रशांत ठाकुर और योगेश पटेल द्वारा प्रकरण की मॉनिटरिंग किए जाने की बात सामने आई,शासन स्तर से विशेष लोक अभियोजक सुरेश शर्मा को मामले की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया था,कुल मिलाकर पुलिस विभाग और शासन के सामने इस मामले में आरोपियों को न्यायालय से दोषसिद्धि तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में लिया गया था, चार आरोपियों की दोषसिद्धि के बाद अब 8 अक्टूबर को होने वाली सजा पर निगाहें हैं,जहां न्यायालय यह तय करेगा कि दोषसिद्ध अपराधों के लिए कानून के तहत कौन-सी सजा निर्धारित की जाती है।

सवाल फिर सामने है—लेकिन अब पुलिस कार्रवाई की जगह न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा है। अब दोषी तय, सिर्फ सजा का इंतजार—इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति यह है कि न्यायालय चार आरोपियों को दोषी करार दे चुका है, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के साथ फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह, चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को दोहरे हत्याकांड में दोषी माना गया है, अब न्यायालय को इन दोषियों की सजा तय करनी है, यानी 8 अक्टूबर की सुनवाई में मूल सवाल यह नहीं होगा कि मामले में दोष सिद्ध हुआ या नहीं—दोषसिद्धि हो चुकी है, अब सवाल सजा की मात्रा और स्वरूप का है, इसीलिए 8 अक्टूबर की तारीख इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तारीख बन गई है।

दोषी करार होने के बाद आरोपी की मुस्कान ने बदल दिया बहस का स्वर—इस मामले में अब एक और दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय है, दोषी करार दिए जाने के बाद मुख्य आरोपी का एक वीडियो सामने आया, वीडियो में वह पुलिस सुरक्षा के बीच न्यायालय से बाहर निकलता दिखाई देता है और उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आती है, गले में मफलर/मगछ भी दिखाई देता है, कुछ ही सेकंड के इस वीडियो ने दो साल पुराने मामले को एक बार फिर लोगों की चर्चा में ला दिया, सवाल उठने लगा कि जिस मामले में दो लोगों की जान चली गई, जिस मामले में दो साल तक न्यायालयीन प्रक्रिया चली और जिस मामले में अब आरोपी दोषी करार दिया जा चुका है, उस स्थिति में आरोपी का मुस्कुराते हुए बाहर आना आखिर क्या संदेश देता है?

सजा के दिन भी मुस्कान—लोगों को क्यों चुभा यह दुश्मन?—लोगों को यह दृश्य इसलिए असहज कर रहा है क्योंकि यह कोई सामान्य आपराधिक मामला नहीं है, यह वही मामला है जिसमें एक परिवार की दो



तत्कालीन आईजी अकित गर्ग



तत्कालीन कोतवाली पुलिस प्रभारी सूरजपुर विमलेश दुबे

तत्कालीन आईजी अकित गर्ग के आश्वासन की भी होगी चर्चा...

इस पूरे मामले के शुरुआती दौर में तत्कालीन आईजी अकित गर्ग ने पुलिस परिवार और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया था कि मामले की जांच प्रभावी तरीके से की जाएगी और आरोपियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने के लिए मजबूत कार्रवाई की जाएगी,उस समय दिया गया यह भरोसा आज दो साल बाद फिर चर्चा में है, अब यदि न्यायालय दोषियों को कठोर सजा देता है तो इसे पुलिस की जांच और उस समय दिए गए आश्वासन के परिणाम के रूप में भी देखा जाएगा,हालांकि न्यायालय का फैसला स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम होगा,किसी पुलिस अधिकारी का आश्वासन अदालत के निर्णय को निर्धारित नहीं करता,फिर भी पीड़ित परिवार के लिए यह जरूर महत्वपूर्ण होगा कि जिस जांच को लेकर उस समय भरोसा दिया गया था,उसका न्यायालयीन परिणाम क्या निकलता है।

फांसी की मांग अपनी जगह,फैसला अदालत का—सूरजपुर के लोगों में इस मामले को लेकर गुस्सा आज भी कम नहीं हुआ है, लोगों का एक वर्ग साफ कह रहा है कि ऐसे अपराध में फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदालत को जनभावना के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करना होगा, क्या अपराध की परिस्थितियां मृत्युदंड के लिए निर्धारित न्यायिक कसौटी तक पहुंचती हैं?

क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उस स्तर की सजा को उचित ठहराते हैं? क्या अदालत कोई अन्य कठोर दंड निर्धारित करती है? इन सवालों का उत्तर अभी किसी के पास नहीं है, उतार केवल 8 अक्टूबर को न्यायालय के आदेश में होगा।

दैनिक घटती-घटना की नजर घटना से फैसले तक— दैनिक घटती-घटना ने इस मामले को घटना के दिन से लेकर न्यायालय के निर्णय तक लगातार अपनी नजर में रखा है,घटना के बाद उज्जैन आक्रोश से लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, न्यायालयीन सुनवाई और अब दोषसिद्धि तक इस पूरे घटनाक्रम को लगातार पाठकों के सामने रखा गया है, अब इस मामले की अंतिम महत्वपूर्ण तारीख सामने है—8 अक्टूबर 2026, उस दिन अदालत क्या फैसला सुनाती है, यह अभी भविष्य के गर्भ में है, शहर फांसी की मांग कर रहा है, पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा में है और पूरा सूरजपुर उस आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है जो दो साल पुराने इस जखम पर न्याय का अमला अग्राह्य लिखेगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है—दोषी करार दिए जाने के बाद अब न्याय की अगली कसौटी सजा है,और 8 अक्टूबर को यह सामने आएगा कि न्यायालय ने इस पूरे अपराध की गंभीरता, परिस्थितियों और सामने रखे गए साक्ष्यों को किस तरह परखा, सूरजपुर पूछ रहा है—जिस वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया, क्या उसकी सजा भी उतनी ही कठोर होगी? जवाब 8 अक्टूबर को अदालत देगी।

8 अक्टूबर सिर्फ एक तारीख नहीं,दो साल के इंतजार का पड़ाव

अब 8 अक्टूबर में कुछ ही दिन बचे हैं,सूरजपुर की नजर जिला न्यायालय पर है,पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है,शहर के लोग सजा को लेकर चर्चा कर रहे हैं,पुलिस विभाग की नजर भी इस फैसले पर होगी, अभियोजन के लिए यह लंबी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है,और न्यायालय के सामने पूरा मामला है—साक्ष्य,गवाह,परिस्थितियां और कानून, यही कारण है कि 8 अक्टूबर को आने वाला फैसला इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होगा।

एक अन्य मामले में 10 साल की सजा और फिर वही चेहरा चर्चा

मे—इसी घटनाक्रम से जुड़े एक अन्य मामले में मुख्य आरोपी को पुलिसकर्मीयों को वाहन से कुचलने के प्रयास के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हो चुकी है, यानी 8 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया का पहला सामना नहीं है, इससे पहले भी अदालत उसके खिलाफ सजा सुना चुकी है, लेकिन उस सजा के बाद सामने आए वीडियो में उसके मुस्कुराते हुए व्यवहार ने अब दोहरे हत्याकांड की आगामी सजा के संदर्भ में भी बहस को और तेज कर दिया है, लोग पूछ रहे हैं की क्या सजा सुनाए जाने का भय आरोपी के व्यवहार में दिखाई देना चाहिए? या फिर न्याय व्यवस्था का उद्देश्य आरोपी के चेहरे पर भय देखना नहीं, बल्कि कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना है? दूसरा सवाल कानूनी रूप से अधिक महत्वपूर्ण है।



त्यागपत्र भी दे दिया, कुर्सी भी छोड़ दी... बस कलम छोड़ना भूल गए!

16 सितंबर को त्यागपत्र... फिर भी सोनपुर में पत्राचार जारी-आखिर यह कैसा त्यागपत्र?

सोनपुर की कुर्सी गई, लेकिन कलम बची रही! त्यागपत्र के बाद भी पत्राचार पर सवाल

- 'पद से त्यागपत्र' या 'कुर्सी से आधी दूरी'? सोनपुर में सहकारिता का नया अध्याय
- त्यागपत्र की चिह्नी सामने आई, लेकिन सोनपुर की फाइलों से श्यामलाल की कलम नहीं हटी!
- बैंक का काम ज्यादा बताया, सोनपुर का पद छोड़ा... फिर भी समिति में आदेश-पत्र क्यों?
- त्यागपत्र दिया, जिम्मेदारी छोड़ी या सिर्फ कागज पर? 'मैं काम करने में असमर्थ हूँ' से 'पत्र जारी' तक—श्यामलाल सिंह के त्यागपत्र पर सवाल...
- त्यागपत्र के बाद भी कर्मचारियों को स्पष्टीकरण! सोनपुर में किस अधिकार से चल रही कलम?
- सोनपुर में नई पंजी, कार्यवाहक सचिव और भुगतान के बाद अब त्यागपत्र—कहानी अभी बाकी!
- प्राधिकृत अधिकारी ने छोड़ा पद, लेकिन सोनपुर की फाइलें नहीं छूटीं—किस आदेश पर जारी हुआ पत्राचार?
- त्यागपत्र स्वीकार हुआ या नहीं? सोनपुर में श्यामलाल सिंह की प्रशासनिक भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल
- कागज पर त्यागपत्र, फाइल में फिर भी हस्तक्षेप? सोनपुर में सवालों की नई पारी
- 16 सितंबर को प्राधिकृत अधिकारी पद से त्यागपत्र, 30 सितंबर की आमसभा में कार्यवाही पंजी पर सवाल, बाद के पत्राचार ने खड़े किए नए प्रश्न

संवाददाता
सोनपुर/भैयाथान, 04 अक्टूबर 2026
(घटना-घटना)।

सहकारिता की कहानी में जब लगा कि सोनपुर समिति का अध्याय अब शायद बंद होने वाला है, तभी एक नया पन्ना सामने आ गया—और इस बार पन्ना खुद त्यागपत्र का है, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर, पंजीयन क्रमांक 580 के प्राधिकृत अधिकारी एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भैयाथान शाखा के शाखा प्रबंधक श्यामलाल सिंह ने 16 सितंबर 2026 को उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के नाम प्राधिकृत अधिकारी पद से त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। त्यागपत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्हें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर का प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन बैंक शाखा के कार्य अधिक होने के कारण वे सोनपुर के प्राधिकृत अधिकारी का कार्य करने में असमर्थ हैं, इसी आधार पर उन्होंने पद से त्यागपत्र देने और उसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है, अब यहां से कहानी में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है जब बैंक का काम इतना ज्यादा था कि सोनपुर का दायित्व निभाना मुश्किल—श्यामलाल सिंह के हस्ताक्षर युक्त त्यागपत्र में तारीख 16.9.2026 अंकित है, पत्र उप पंजीयक महोदय को संबोधित है और विषय में 'सोनपुर समिति से प्राधिकृत पद से त्याग पत्र स्वीकार करने बाबत' लिखा गया है, पत्र की भाषा में उन्होंने कहा है कि उन्हें सोनपुर समिति का प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन बैंक शाखा का कार्य अधिक होने के कारण सोनपुर का प्राधिकृत अधिकारी का कार्य करने में असमर्थ हैं, यानी खुद उनके त्यागपत्र का आधार यही है कि एक तरफ बैंक शाखा की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ सोनपुर समिति की जिम्मेदारी—दोनों को साथ निभाना उनके लिए संभव नहीं था, अब व्यंग्य यहीं से शुरू होता है, अगर काम इतना ज्यादा था कि समिति का दायित्व निभाना मुश्किल था तो फिर सवाल यह है कि इस दौरान समिति में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जिम्मेदारी किसकी थी? और यदि जिम्मेदारी निभाई जा रही थी तो त्यागपत्र में 'असमर्थ' होने की वजह क्यों? सहकारिता की इस कहानी में अब शायद एक नया फार्मूला सामने आया है... बैंक का काम ज्यादा हो तो समिति छोड़ दीजिए, लेकिन समिति छोड़ने के बाद भी अगर कलम चलती रहे तो उसे किस श्रेणी में रखा जाए?

त्यागपत्र दिया है, लेकिन स्वीकार हुआ या नहीं... सबसे पहले यही स्पष्ट हो—यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी-प्रशासनिक अंतर है, त्यागपत्र देना और त्यागपत्र स्वीकार होना एक ही बात नहीं है, उपलब्ध पत्र से इतना स्पष्ट है कि श्यामलाल सिंह ने 16 सितंबर को त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया है, लेकिन इस पत्र से अकेले यह साबित नहीं होता कि उप पंजीयक ने उसी दिन या बाद में उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था, यही अब विभाग के सामने सबसे पहला सवाल है क्या 16 सितंबर का त्यागपत्र स्वीकार किया गया? यदि स्वीकार किया गया तो किस तारीख से? यदि स्वीकार नहीं किया गया तो क्या श्यामलाल सिंह तब तक प्राधिकृत अधिकारी के अधिकारों का उपयोग करते रहे? यदि कोई अलग आदेश जारी हुआ तो वह क्या था? और यदि त्यागपत्र लंबित था तो उसके बाद जारी पत्र किस अधिकारी के तहत जारी हुए? इसका जवाब केवल त्यागपत्र की स्वीकृति संबंधी कार्यालयीन आदेश से मिल सकता है।

त्यागपत्र के बाद भी पत्राचार—यही तो नई पहली है—अब इस मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है, एक तरफ 16 सितंबर का त्यागपत्र, दूसरी तरफ उसके बाद सोनपुर समिति से कर्मचारियों के संबंध में पत्राचार और कार्रवाई होने की जानकारी, यदि यह तथ्य दस्तावेजों से पुष्ट होता है तो सवाल गंभीर है, क्या श्यामलाल सिंह का त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ था? या उन्हें किसी अन्य आदेश के तहत कार्य जारी रखने को कहा गया था? या फिर प्राधिकृत अधिकारी पद से त्यागपत्र देने के बावजूद कुछ प्रशासनिक कार्य उनके पास बने रहे? या फिर उनके द्वारा जारी पत्र किसी अन्य अधिकार के आधार पर जारी किए गए? इनमें से कौन-सी स्थिति सही है, इसका उत्तर विभाग को देना चाहिए, क्योंकि सहकारिता में पद की कुर्सी और पद की कलम दोनों की अपनी वैधानिक सीमा होती है।

30 सितंबर की आमसभा ने फिर खोल दी 'पंजी' की फाइल—अब आते हैं 30 सितंबर की उस वार्षिक साधारण आमसभा पर, जहां सोनपुर समिति के सदस्यों और किसानों ने कथित तौर पर ऐसे सवाल उठाए, जिन्होंने पहले से चल रहे विवाद को फिर सामने ला दिया, बैठक में मांग की गई कि समिति की कार्यवाही पंजी उपलब्ध कराई जाए, सवाल यह था कि आखिर संस्था में बार-बार नई कार्यवाही पंजी क्यों संधारित की गई? किसके आदेश से? किस परिस्थिति में? क्या मूल कार्यवाही पंजी उपलब्ध थी? यदि उपलब्ध थी तो नई पंजी क्यों? और नई पंजी में लिए गए फैसलों का पुरानी कार्यवाही से क्या संबंध है? जब आमसभा में सदस्य ही संस्था की कार्यवाही का मूल रिकॉर्ड मांग रहे हों, तो इसे मामूली सवाल कहकर टाला नहीं जा सकता।

नई पंजी, एक दिन का कार्यवाहक सचिव और फिर कर्मचारी की वापसी—सोनपुर समिति से जुड़े पूर्व घटनाक्रम में आरोप



है कि 7 अगस्त 2026 की बैठक में नई कार्यवाही पंजी संधारित की गई और एक दिन के लिए कार्यवाहक सचिव/प्रबंधक की व्यवस्था की गई, इसके बाद विवादित कर्मचारी विवेक कुमार चौरसिया को पुनः कार्य पर रखने का निर्णय लिए जाने की बात सामने आई, अब आमसभा में किसानों का सवाल यही बताया जा रहा है जिस कर्मचारी की नियुक्ति पर पहले से सवाल थे, उसे वापस रखने से पहले उसकी मूल नियुक्ति फाइल देखी गई थी या नहीं? क्या नियुक्ति आदेश था? क्या पद स्वीकृत था? क्या विज्ञापन हुआ था? क्या चयन प्रक्रिया हुई थी? क्या बोर्ड की अनुमति थी? क्या सेवा समाप्ति के कारणों की समीक्षा की गई? क्या पुनर्नियुक्ति से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई? यदि इन सभी प्रश्नों के दस्तावेज उपलब्ध हैं तो उन्हें आमसभा में रखने में समस्या नहीं होनी चाहिए।

फिर 5 सितंबर—नई पंजी और भुगतान का दूसरा अध्याय—मामला यहीं नहीं रुका, आरोप है कि 5 सितंबर 2026 को फिर नई कार्यवाही पंजी संधारित की गई और कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित निर्णय लिए गए, कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को पूर्व की अवधि के लंबित वेतन के नाम पर समिति के बचत खाते से लाखों रुपये का भुगतान किया गया, अब यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल 7 अगस्त की कथित कार्यवाही से जुड़ता है, बताया गया है कि 7 अगस्त की बैठक में विवेक चौरसिया की पृथक अवधि के वेतन भुगतान के लिए उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं सुरजपुर से अनुमति प्राप्त करने के बाद भुगतान किए जाने की बात कही गई थी, तो सवाल है—क्या अनुमति ली गई? अगर ली गई तो आदेश कहा है? कितनी राशि की अनुमति मिली? क्या उसी अनुमति के आधार पर भुगतान हुआ? यदि अनुमति नहीं ली गई तो 5 सितंबर का भुगतान किस आधार पर हुआ?

बर्खास्तगी या अनुपस्थिति अवधि का वेतन—किस नियम से?—आमसभा में उठे सवालों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों को किए गए भुगतान से जुड़ा बताया जा रहा है, यदि कोई कर्मचारी बर्खास्त था, सेवा से पृथक

था या लंबे समय तक संस्था के कार्य से अनुपस्थित था तो उसकी उस अवधि की वेतन देयता किस आधार पर तय हुई? क्या उपस्थिति रजिस्टर देखा गया? क्या सेवा पुस्तिका देखी गई? क्या अनुपस्थिति स्वीकृत थी? क्या कोई न्यायालय अथवा सक्षम अधिकारी का आदेश था? क्या वेतन भुगतान की गणना की गई? क्या उच्च कार्यालय की अनुमति ली गई? अगर सब कुछ नियम के तहत था तो पूरा दस्तावेजी रिकॉर्ड सामने आना चाहिए।

आमसभा में किसानों का सवाल—'हमें पंजी दिखाइए'—30 सितंबर की आमसभा में कथित तौर पर यही सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा कि संस्था की मूल कार्यवाही पंजी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए, सदस्यों ने यह भी पूछा कि आखिर बार-बार नई पंजी क्यों तैयार की गई और उन्हीं पंजी में ऐसे फैसले क्यों दर्ज हुए जिनका सीधा असर कर्मचारी नियुक्ति और समिति के वित्तीय भुगतान पर पड़ा, बताया गया है कि पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उपस्थित सदस्यों ने बैठक का विरोध किया और आमसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी, यदि यह स्थिति आधिकारिक कार्यवाही में दर्ज है तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है, क्योंकि आमसभा वह मंच है जहां सदस्य संस्था के कामकाज पर सवाल उठा सकते हैं।

सोनपुर में अब सवाल यह नहीं कि पंजी कितनी है, सवाल है—मूल पंजी कौन-सी है?—एक संस्था में कार्यवाही पंजी का उद्देश्य ही निर्णयों का क्रमबद्ध रिकॉर्ड रखना है, लेकिन यदि किसी संस्था में अलग-अलग महत्वपूर्ण बैठकों के लिए नई पंजी सामने आती रहे तो सवाल उठना स्वाभाविक है, मूल पंजी कौन-सी है? नई पंजी कब खोली गई? किसने प्रमाणित की? उसका क्रमांक क्या है? पुरानी पंजी में अंतिम कार्यवाही क्या दर्ज है? नई पंजी में पहली कार्यवाही क्या है? और दोनों के बीच रिकॉर्ड का क्रम कैसे जुड़ता है? इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही पता चलेगा कि नई पंजी बनाना सामान्य प्रक्रिया थी या कोई विशेष परिस्थिति।

श्यामलाल सिंह का त्यागपत्र—क्या विवादों के बीच आया प्रशासनिक मोड़?—अब श्यामलाल सिंह के त्यागपत्र को भी इसी पूरे घटनाक्रम के बीच देखा जा रहा है, लेकिन यहां सावधानी जरूरी है, त्यागपत्र पत्र में उन्होंने खुद बैंक शाखा के कार्य अधिक होने को कारण बताया है, पत्र में यह नहीं लिखा है कि उन्होंने किसी दबाव, शिकायत, विवाद या समाचार प्रकाशन के कारण त्यागपत्र दिया, इसलिए यह कहना कि उन्होंने किसी दबाव में त्यागपत्र दिया, बिना अतिरिक्त प्रमाण के उचित नहीं होगा, हॉ, यह जरूर पूछा जा सकता है कि त्यागपत्र देने का समय क्या था? क्या उस समय उनके खिलाफ कोई शिकायत लंबित थी? क्या किसी मामले में उनसे जवाब मांगा गया था? क्या कोई जांच चल रही थी? और सबसे महत्वपूर्ण—त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद उनकी

किसके दबाव में?... अब यह सवाल दस्तावेजों से पूछना होगा...

सोनपुर समिति के घटनाक्रम में यह चर्चा भी सामने आती रही है कि श्यामलाल सिंह पर किसी विरिष्ट व्यक्ति का दबाव था और उनसे नियम विरुद्ध काम करवाया जा रहा है? इसलिए जांच का रास्ता सीधा है, फाइल नोटिंग देखिए, आदेश देखिए, पत्राचार देखिए, क्लॉकसप निर्देश हैं तो उनका परीक्षण कीजिए, किसने बैठक कराने कहा? किसने कर्मचारी को वापस रखने कहा? किसने भुगतान की अनुमति दी? किसने पत्र जारी करने कहा? फाइल में यदि कोई दबाव है तो वह दिखाई देगा, यदि नहीं है तो यह आरोप भी वहीं खत्म हो जाएगा।

प्रशासनिक भूमिका क्या रही? और अब एक बड़ा सवाल—त्यागपत्र के बाद भी 'सोनपुर' क्यों नहीं छूटा?—यही सवाल पूरे प्रकरण का सबसे व्यंग्यात्मक हिस्सा है कि श्यामलाल सिंह कहते हैं बैंक शाखा का काम अधिक है, इसलिए सोनपुर का प्राधिकृत अधिकारी का कार्य करने में असमर्थ हूँ, ठीक है, लेकिन यदि उसके बाद भी सोनपुर से जुड़े कर्मचारियों को पत्र जारी हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और भुगतान संबंधी प्रक्रिया में उनका नाम सामने आ रहा है, तो फिर सवाल होगा कि बैंक का काम ज्यादा था या सोनपुर की फाइल का आकर्षण ज्यादा? बेशक यह केवल व्यंग्यात्मक सवाल है पर वास्तविक स्थिति दस्तावेजों से ही तय होगी, लेकिन आमसभा में किसानों के सवालों और त्यागपत्र के पत्र को साथ रखकर देखें तो यह सवाल अपने आप पैदा होता है कि जिम्मेदारी छोड़ने की कोशिश और उसके बाद की प्रशासनिक भूमिका में आखिर संबंध क्या था?

शिवप्रसादनगर से सोनपुर तक—अब वित्तीय रिकॉर्ड भी जांच की मांग कर रहे हैं—दूसरी तरफ शिवप्रसादनगर समिति के बचत खाते से बड़े भुगतान को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, आरोप है कि समिति के खाते से बड़ी राशि निकाली गई और खर्चों को लेकर पारदर्शिता नहीं रही, इन आरोपों को तथ्य मानने से पहले बैंक स्टेटमेंट, बिल, वाउचर, भुगतान प्रस्ताव और वास्तविक खर्च का मिलान जरूरी है, इसी तरह आमसभा में यह सवाल भी उठना जाना चाहिए कि क्या बचत खाते से हुए बड़े भुगतानों का विवरण सदस्यों को दिया गया? क्या हमाल भुगतान की जानकारी दी गई? क्या किसानों द्वारा कथित रूप से किए गए भुगतान और समिति द्वारा किए गए भुगतान का मिलान कराया गया? क्या सदस्यों को आय-व्यय का विवरण उपलब्ध कराया गया? यदि आमसभा में यह सब प्रस्तुत हुआ था तो रिकॉर्ड सामने आए, यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ?

अब विभाग के सामने एक नहीं, पूरी प्रश्नावली है—सोनपुर मामले में अब सवालों की सूची लंबी हो चुकी है, श्यामलाल सिंह ने त्यागपत्र कब दिया? क्या त्यागपत्र स्वीकार हुआ? यदि स्वीकार हुआ तो किस तारीख से? उसके बाद उन्होंने कौन-कौन से पत्र जारी किए? क्या वे पत्र प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार से जारी हुए? 7 अगस्त की नई कार्यवाही पंजी किस आदेश से बनी? एक दिन का कार्यवाहक सचिव किस आदेश से

नियुक्त हुआ? विवेक चौरसिया को पुनः कार्य पर रखने से पहले मूल नियुक्ति दस्तावेजों की जांच हुई या नहीं? 5 सितंबर की नई कार्यवाही पंजी क्यों बनी? कर्मचारियों को किस आधार पर भुगतान किया गया? क्या उच्च कार्यालय की अनुमति ली गई? 30 सितंबर की आमसभा में मूल पंजी क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई? बैठक स्थगित होने की वास्तविक वजह क्या थी? इन सभी सवालों का उत्तर एक ही जगह से आ सकता है—मूल दस्तावेजों से। सोनपुर में अब 'त्यागपत्र' से ज्यादा जरूरी है अधिकार की स्थिति स्पष्ट करना—श्यामलाल सिंह का त्यागपत्र अपने आप में कोई अपराध या अनियमितता का प्रमाण नहीं है, बैंक शाखा के अधिक कार्यभार के कारण किसी अतिरिक्त दायित्व से मुक्त होने का अनुरोध करना प्रशासनिक रूप से संभव है, लेकिन जब उसी समिति में उनके कार्यकाल के दौरान कई विवादित फैसलों पर सवाल उठ चुके हों और त्यागपत्र के बाद भी पत्राचार की बात सामने आए, तो प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए उनकी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है।

आमसभा स्थगित हुई है, सवाल नहीं...

30 सितंबर की आमसभा भले ही स्थगित हुई हो, लेकिन उसने सोनपुर समिति की सबसे महत्वपूर्ण फाइल फिर खोल दी है, किसान अब सिर्फ यह नहीं पूछ रहे कि कर्मचारी कौन है, वे पूछ रहे हैं—पंजी कौन-सी है? निर्णय किसके हैं? कार्यवाहक सचिव किस आदेश से आया? कर्मचारी किस प्रक्रिया से वापस आया? वेतन किस आधार पर मिला? त्यागपत्र के बाद कलम किस अधिकार से चली? और सबसे महत्वपूर्ण—'अगर प्राधिकृत अधिकारी ने 16 सितंबर को कह दिया कि बैंक का काम अधिक होने के कारण सोनपुर का दायित्व निभाना संभव नहीं है, तो 30 सितंबर तक सोनपुर की फाइलों में उनकी भूमिका आखिर किस रूप में बची रही? अब सहकारिता विभाग के पास दो ही रास्ते हैं—या तो पूरी फाइल खोलकर हर सवाल का दस्तावेजी जवाब दे, या फिर सवालों को और बढ़ा होने दे, क्योंकि सोनपुर की आमसभा ने बैठक भले स्थगित की है, लेकिन 'नई पंजी, नया सचिव, नया भुगतान और अब त्यागपत्र' वाला अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है।



